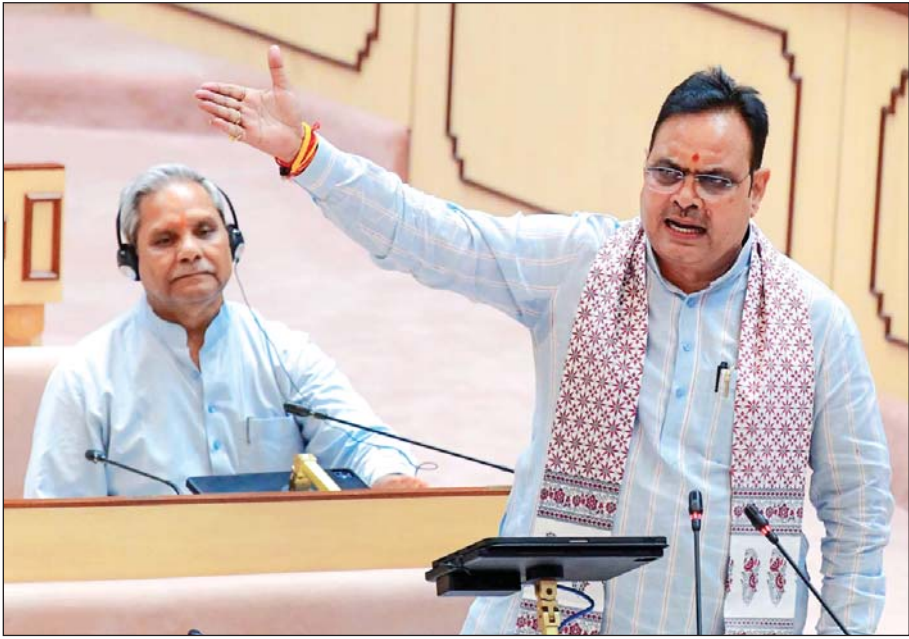


# ‘विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, बहस करते तो 5 साल की सच्चाई सामने आ जाती’

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में अपनी सरकार के दो साल के काम की रिपोर्ट कार्ड रखते हुए टिप्पणी की

जयपुर, 21 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड रखा था। शर्मा ने शनिवार को सदन में कहा कि हर सरकार का दायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की

- **मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 626 ऐसी घोषणाएं कीं, जिन पर काम शून्य रहा, ये सब लोक लुभावन घोषणाएं थीं।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी 90 प्रतिशत बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं या शुरु हो चुकी हैं।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को विधानसभा में दो साल के कामकाज का जवाब दिया।

125 करोड़ से पांच गोलफ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर ‘काम ज़ीरो’ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए, राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है, बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं कीं, जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार

के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक हैं। शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया “गिवअप” अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ईकेवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन

निर्माण किया है, जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए, जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है।

शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दीं, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थीं। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

## ‘भारत के साथ ट्रेड ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) रमेश ने कहा कि 2 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि वे इससे खुश हैं और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम की समय-रेखा महत्वपूर्ण है। जयराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के बहुमत से, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित निर्णय में, ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति ने व्यापक शुल्क लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। रमेश ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गौयल को दिसंबर से ही संभावित फैसले की जानकारी थी और यह आशंका थी कि टैरिफ रद्द हो सकते हैं, तो फिर इतनी जल्दबाजी में समझौता

## राहुल ने कई इन्टरव्यू ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) डोनाल्ड के बीच कड़े मतभेद की चर्चाएं भी रही हैं। गौरलतल है कि 2007 से राहुल गांधी एएमएसयूआई और युवा कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए साक्षात्कार, चयन और चुनाव प्रक्रिया

क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत टैरिफ आयात पर 150 दिनों के लिए लागू होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के ढांचे में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्ष द्वारा बदलाव की स्थिति में दोनों देश अपनी प्रतिबद्धताओं में संशोधन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत डंडात्मक टैरिफ को हटा दिया था। इसके साथ ही, वॉशिंगटन ने नई दिल्ली पर पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।

में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। लेकिन इस कवायद से अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता उभरकर सामने नहीं आया है, जबकि अतीत में युवा कांग्रेस से प्रशिक्षण पाकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हुए थे।

# शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

## दुष्कर्म एवं पॉक्सो कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है

प्रयागराज, 21 फरवरी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण आरोप के मामले में एंडीजे दुष्कर्म एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एंडीजे पॉक्सो एक्ट के शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद अब झुंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने को कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने न्यायालय में 173 (4) के तहत वाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की

- **इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा एफआईआर हो और जांच हो तभी सच्चाई सामने आएगी।**

मांग की थी। इस संबंध में 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज हुए थे। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस की रिपोर्ट की संज्ञान में लेने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने

## ‘हर साल हजारों करोड़ रु. दान कर देते हैं भारतीय’

नई दिल्ली, 21 फरवरी। भारत में रहने वाले लोग हर साल हजारों करोड़ रुपये दान में दे देते हैं। इस बात का खुलासा “हाउ इंडिया गिक्स” रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में हुआ है।

इसमें व्यक्तिगत दान का 45.9 प्रतिशत हिस्सा धार्मिक संगठनों को जाता है। 41.8 प्रतिशत दान सीधे बेहद

- **“हाउ इंडिया गिक्स” रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार सबसे ज्यादा 45.9 प्रतिशत दान धार्मिक संगठनों को जाता है और 41.8 प्रतिशत सीधे जरूरतमंदों को दिया जाता है। गैर धार्मिक संगठनों को 14.9 प्रतिशत दान जाता है।**

गरीब, जरूरतमंद व भिक्षा मांगने वालों को मिलता है। गैर-धार्मिक संगठनों तक सिर्फ 14.9 प्रतिशत दान पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में दान का सबसे बड़ा आधार आम घर है। कुल घरेलू दान का अनुमान हर साल 54 हजार करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 68 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी रूप में देने की बात कही।

# रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की

## अजित पवार के भतीजे रोहित ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की

- **पवार ने कहा जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके प्रमोटरों से मंत्री राममोहन नायडू के निकट संबंध हैं, उन्हें हटाए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।**

मुंबई, 21 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। रोहित पवार ने तर्क दिया है कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जान लेने वाली विमान दुर्घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्री का पद से हटना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रोहित पवार ने ‘हितों के टकराव’ का गंभीर मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस विमान कंपनी (वीएसआर वेंचर्स) का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके प्रमोटरों और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी (टीडीपी) के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटना से ठीक पहले विमान के डेटा और उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित कंपनी के रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों की जांच में पारदर्शिता की कमी है।

रोहित पवार ने स्पष्ट किया है कि

यह केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है। चूंकि यह एक उच्च-स्तरिय सुरक्षा चुक का मामला है, इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पत्र की प्रति भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक, दुर्घटना के समय सिर्फ एक

धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे।

विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए।

जिस सीवीआर की हम बात कर रहे हैं, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, उसकी उस उड़ान में रिकॉर्डिंग क्षमता केवल 30 मिनट की थी। लेकिन यदि आप सरकारी नियमों को देखें, तो डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की आवश्यकता दो घंटे की रिकॉर्डिंग की है। तो अगर विमान का सीवीआर केवल 30 मिनट रिकॉर्ड कर सकता था, जबकि नियम दो घंटे का है, तो उस विमान का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? यह बात हम सभी जानना चाहते हैं।

यह दुर्घटना से पहले के अंतिम 30 मिनटों का रिकॉर्ड है, यानी यह आखिरी दर्ज किया गया हिस्सा है। उन अंतिम 30 मिनटों में क्या हुआ, इसकी जानकारी केवल सीवीआर से ही मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सीवीआर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है।

# ममता बनर्जी के साथ मंच पर नज़र आए भाजपा सांसद नागेन रॉय

## रॉय ने केन्द्र पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया

- **अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर तेज हो सकता है।**

कोलकाता, 21 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद नागेन रॉय उर्फ अनंत महाराज राजबंशी समुदाय के नेता हैं। उनको शनिवार को शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं।

महाराज के संबंध हाल के महीनों में भाजपा के साथ तनावपूर्ण रहे हैं। मंच पर बैठे और वरिष्ठ मंत्रियों व टीएमसी नेताओं ने आरोप बिस्वास और इंद्रनील

सेन के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, आपकी मौजूदगी से हमें सम्मान मिला है। खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री के रूप में बनर्जी का यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं

## दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट

नई दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस खुफिया जानकारी के बाद राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान

- **खुफिया जानकारी मिली है कि लश्करे तैयबा दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है।**

समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलएटी) दिल्ली में आईईटी हमले की साजिश रच रहा है।

सूत्रों के अनुसार, आतंकियों के निशाने पर ऐतिहासिक लाल किला स्थित मंदिर और उसके आसपास का इलाका हो सकता है।

खासकर भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक स्थित प्रमुख मंदिर को लेकर इनपुट मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी विशेष स्थल का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

# 5 लाख रु. की रिश्वत लेते पकड़े गए भाजपा विधायक

नई दिल्ली, 21 फरवरी। कर्नाटक के शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्र लमानी को कर्नाटक लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। उन पर पकड़े गये 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अधिकारियों ने बताया कि लमानी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, फिर पछुताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उनके दो पर्सनल असिस्टेंट को भी हिरासत में लिया गया है।

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, यह रिश्वत कथित तौर पर गडग जिले में छोटे सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी मंजूरी दिलाने के लिए मांगी गई थी। इस काम के तहत शिफ्ट के दोनों तरफ एक रेटेंगिंग वॉल (सहायक दीवार) बनानी थी। शिकायत करने वाले गडग के क्लास-1 कॉन्स्ट्रक्टर विजय पुजार से जब कथित तौर पर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेने के लिए 11 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने एंटी-कorrप्शन अधिकारियों से संपर्क किया।

## एआई इम्पैक्ट का ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) कोरिया, इजरायल, ईरान, ब्राजील, मिश्र, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई, स्पेन सहित, पड़ोसी देश न्याम्रा, श्रीलंका ने हस्ताक्षर किये हैं। 86 देशों के साथ दो संगठन, यूरोपीय यूनियन और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड ने भी हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा पत्र के तहत आधारभूत संसाधनों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित कर स्थानीय नवाचार

## भारत पर अमेरिकन टैरिफ 1 8 ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) सहमत हुए हैं। लेकिन, वाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन आगे चलकर “अधिक उपयुक्त या पूर्व-निर्धारित टैरिफ दरें लागू करने” के विकल्प तलाशेगा। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी। इससे पहले, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत डंडात्मक टैरिफ को हटाय़ा था और नई दिल्ली पर रैसिप्रोकल शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।

अब 10 प्रतिशत की नई वैश्विक दर, जो दुनिया के सभी देशों पर लागू होगी, लागू होने के बाद, अमेरिका में आयातित भारतीय वस्त्रों पर पहले तय 18 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं रहेगा। लेकिन धारा 122 के तहत लगाए गए ये टैरिफ 150 दिनों के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि कांग्रेस इन्हें बढ़ाने के लिए मतदान न करे। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यद्यपि

समय-सीमा स्पष्ट है, लेकिन राष्ट्रपति इन उपायों को समाप्त होने दे सकते हैं और फिर नए धुगतान संतुलन आपातकाल की घोषणा कर पुनः लागू कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह राष्ट्रपति की व्यापार नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उनके चुनाव अभियान और एजेंडे का केन्द्रीय हिस्सा रही है।

## जेवर में सेमीकंडक्टर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर तीव्र गति से कार्य कर रहा है। उन्होंने लाल किले से दिए अपने संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पास रुकने या ठहरने का समय नहीं है। वर्ष 2026 की शुरुआत से ही देश ने विकास की रफ्तार और तेज कर दी है।

उन्होंने बताया कि भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 10 फैब्रिकेशन और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से

इसी बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि अब से तुरंत प्रभाव से दुनिया के सभी देशों से होने वाले आयात पर लगाने वाला टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया जाएगा।

कोरोना महामारी के दौरान चिप सप्लाई चेन में आई बाधाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने उस संकट से सीकवर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया।